(d) if so, the details of such dialogue; and

(e) if not, how do Government propose to popularise this concept of "e-Commerce"?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI RAMAKRISHNA HEGDE): (a) and (b) Institutional set up in the form of Electronic Commerce (EC) Council, India EDIFACT Committee, EC Working Group and Message Development Groups for Customs, Ports, Airports, Finance and Private Sector have been created for promotion and propagation of EC/Electronic Data Interchange (EDI) for trade with special reference to International Trade. Committees on Process Re-engineering and Legal were also formed. The coordinated EC/EDI implementation is going on for trade regulatory organisations which is periodically reviewed in sectoral EC/EDI review committees. In private sector pilot project have been initiated in automobile sector. This is proposed for replication to other sectors. Regular Awareness and education programmes are conducted. Article numbering organisation has been created for integration of Automatic Data Capturing Techniques into EC and a Technical Assessment Group is formed for the development and assessment of EDI messages.

(c) to (e) reference has been made to Cheif Secretary, Govt. of Andhra Pradesh to Automate International Cargo Management functions and implement EDI based system adopt automatic data capturing tools in State run organisations and also to integrate cargo clearance activities with community partners. Customs, Port Trust and other implementing agencies are also implementing ED/EC at various locations in the country including Andhra Pradesh.

**Import Policy on Dairy Products**

1244. SHRI JALALUDIN ANSARI:
SHRI GURUDAS DASGUPTA:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item captioned "NDDB seeks import policy on dairy products", which appeared in the Times of India, dated the 8th February, 1999; and

(b) if so, the details thereof and Governments' reaction thereto?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI RAMAKRISHNA HEGDE): .(a) yes, Sir.

(b) The import of milk, except skimmed milk and its products, is restricted. However, free import of these items is permitted from SAARC countries. The import of skimmed milk is allowed freely at zero tariff rate to supplement the availability of milk in the country.

The future import policy on dairy products will not only depend on India's large domestic requirement but also our commitment to phase out import res:rictions by the year 2003.

**यूरोपीय देशों को चाय का निर्यात**

1245. **श्री रमा शंकर कौशिकः**
**प्रो॰ रामगोपाल यादवः**

**क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में भारत द्वारा निर्यातित चाय की खेप को यूरोपीय देशों द्वारा वापस भेज दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और इससे भारत को कुल कितना आर्थिक नुकसान हुआ है; और

(ग) भारत को हुए इस आर्थिक नुकसान के लिए कौन उत्तरदायी है और सरकार द्वारा उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

**वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े)**: (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**व्यापार व वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए वार्ता**

1246. **प्रो॰ राम बख्श सिंह वर्मा:**
**श्रीमती मालती शर्मा:**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार एवं वाणिज्यिक सहयोग बढ़ाने के संबंध में सचिव स्तर पर वार्ता हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच जिन क्षेत्रों के संबंध में समझौते हुए हैं उनका ब्यौरा क्या है?

**वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े):** (क) से (ग) जी, हां, 23 जून, 1997 की समस्त कार्यसूची के आधार पर भारत और पाकिस्तान के बीच संयुक्त और समेकित वार्ता प्रक्रिया के एक भाग के रूप में दिनांक 10 नवम्बर, 1998 को दिल्ली में आर्थिक एवं वाणिज्यिक सहयोग पर विचार-विमर्श आयोजित किए गए थे। उक्त विचार-विमर्श वाणिज्य सचिव के स्तर पर आयोजित किए गए थे।

दोनों शिष्टमंडलों ने वाणिज्यिक एवं आर्थिक सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विचारों का आदान-प्रदान किया। दोनों पक्षों ने अंतराष्ट्रीय मचों पर सामाजिक खण्डों, पर्यावरणिक मुद्दों इत्यादि जैसे क्षेत्रों में समन्वित दृष्टिकोण तैयार करने के लिए विचार-विमर्श का सिलसिला आगे और बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने बकाया राशियों के समाधान के लिए उपयुक्त क्रियाविधि का पता लगाने के लिए सहमति व्यक्त की। इस बात पर भी सहमति हुयी थी कि रेल मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के तकनीकी दल इन क्षेत्रों में वाणिज्यिक सहयोग के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए दौरा करेंगे। यह निर्णय लिया गया था कि भविष्य में आगे और वार्ताएं आयोजित की जानी चाहिए। तथापि, इन वार्ताओं के दौरान किसी भी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

**सोने का आयात**

1247. **श्री कपिल सिब्बल:**
**श्री राज मोहिन्दर सिंह:**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात के मुकाबले आयात अधिक होने का अनुमान है;

(ख) यदि हां, तो आयात निर्यात मूल्यों के संबंध में क्या अनुमान है;

(ग) क्या यह भी सच है कि आयात में यह वृद्धि सोने के आयात के कारण हुई है; और

(घ) यदि हां, तो आयातित सोने का मूल्य कितना है और स्वर्णाभूषणों-जेवरातों आदि के निर्यात से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है?

**वाणिज्यिक मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) जी, हां।**

(ख) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-जनवरी, 98-99 के दौरान भारत का आयात और निर्यात क्रमशः 34952 मिलियन डालर और 27158 मिलियन अमरीकी डालर रहा है।

(ग) और (घ) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-नवम्बर, 98 के दौरान सोने का आयात 2983 मिलियन अमरीकी डालर का हुआ है। इसी अवधि के दौरान रत्न तथा आभूषण का निर्यात 3723 मिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है।

**प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध**

1248. **श्री राज मोहिन्दर सिंह:**
**श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में प्याज की कीमतों को गिरने से रोकने के लिए किए गए अनुरोध पर सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाए जाने के समय देश में प्याज का औसत थोक मूल्य कितना था; और